रोड़ सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं के समाधान के लिए बने केंद्रीय स्तर पर स्थाई सचिवालय

– सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री

जयपुर, 11 जनवरी। सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री श्री युनूस खान ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि रोड़ सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं के समाधान के लिए केंद्रीय स्तर पर स्थाई सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए।

श्री खान मंगलवार को नई दिल्ली के इंडिया हेबीटेट सेंटर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की 17वीं बैठक में बोल रहे थे।

उन्होने बताया कि सड़क सुरक्षा एवं सड़क परिवहन क्षेत्र की बेस्ट प्रेक्टिसेस की समीक्षा के लिए बनाये गये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इस अनुशंषा का अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किया हैं।

श्री खान ने सुझाव दिया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्यों को विदेशों के सड़क सुरक्षा मॉडल्स का अध्ययन करने के लिए भिजवाया जाना चाहिए। उन्होने ''नेशनल रोड़ सेफ्टी ट्रेफिक मेनेजमेंट बोर्ड'' बनाने का सुझाव भी दिया। साथ ही वाहन चालकों के लिए दुर्घटना बीमा करवरेज दिलवाने तथा एकीकृत रोड़ सुरक्षा दिशा निर्देश बनाने का आग्रह किया, ताकि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो सके।

श्री खान ने विभिन्न लाइसेंस एवं प्रमाण पत्रों के लिए शुल्क एवं जांच शुल्क तय करने का अधिकार राज्यों को देने का सुझाव दिया।

राजस्थान ने स्थापित किए नये आयाम

उन्होने राजस्थान में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा सुधारों और अभियानों की चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अपनी ''सड़क सुरक्षा नीति'' बनाई है जिसके तहत स्कूलों में 6 से 12 कक्षा तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा के पाठ जोड़े गये है।

उन्होने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्यव्यापी एकीकृत जन जागृत्ति अभियान चलाये गये है। परिणाम स्वरूप गतवर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्युओं में कमी आई है। सड़क सुरक्षा अभियान को अब राज्य के संभागीय स्तर पर भी चलाया जायेगा।

श्री खान ने उम्मीद जताई कि श्री गडकरी के नेतृत्व में चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा के सुधार उपायों के फलस्वरूप हम एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगें जो पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा तथा वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाने के लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब हो सकेगा। साथ ही वाहनों के पहियों पर उचित नियंत्रण के जरिए देश के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के चक्र को भी और अधिक गतिमान किया जा सकेगा।

बैठक में राज्य के प्रमुख परिवहन सचिव श्री शैलेंद्र अग्रवाल और पुलिस महानिरीक्षक श्री बी.एल सोनी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (एन.एच) श्री ए.के गर्ग भी मौजूद थे।

—